industry. The Group submitted an interim report on 3rd May, and its final report on 24th July, 1968. The recommendations of the Group are primarily intended in respect of mills which are unable to provide normal margins but whose financial condition is otherwise sound. The recommendations relating to the reduction in the margin for the grant of advances against the security of cotton, cloth, yarn and stores and also fixed assets have been brought to the notice of the commercial banks. They have been advised not to turn down loan applications merely because the mills cannot provide the normal margins. Details of applications which are rejected are required to be reported to the Reserve Bank in order to review the decisions, if necessary. Further in cases where the cotton textile mills have diverted a part of their cash credit facilities for the acquisition of fixed assets, the Industrial Development Bank has decided to extend refinancing facilities in respect of a part of such advances. The other major recommendations of Group relate to the provision of additional credit by the term lending institutions for the purpose of modernisation of plant and machinery, grant of loans in deserving cases for modernisation/expansion on an easier repayment schedule, extension of time limit for compliance with the Reserve Bank's direction for liquidation of excess public deposits held by textile mills and provision of Government guarantee in marginal cases. These recommendations are not of general applicability and each case has to be processed on its merits.

कोयना बांध के निकट भूचाल के झटके

1641. **श्री भोला नाथ मास्टर :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कोयना बांध के निकट हाल ही में भूचाल के झटके पुनः आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किस तरह के थे ; और

(ग) इस झटकों से उस क्षेत्र में लोगों के माल व जान की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 11 दिसम्बर, 1967 के प्रमुख भूकम्प के पश्चात् भी, कोयना क्षेत्र में कई झटके आते रहे । इन में से कुछ झटके बहुत तेज थे और कुछ मध्यम व कम तीव्रता के थे । परन्तु बाद के इन झटकों से कोयना क्षेत्र में कोई क्षति नहीं हुई है ।

(ग) युनेस्को के मेल-जोल में, भारत द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर, कोयना बांध की मरम्मत के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) इपाक्सी बराजो और पोल्येस्टर पदार्थों से बांध में दरारों की भराई ।

(2) बाघ के मुख्य भाग में द्रव-स्थैतिक दाबों को दूर करने के लिए निकासी सुराखों का छेदना ।

(3) बी० आर० सी० पे-ब्रिक जाल से पुनर्बलित गुनाइटिंग की एक तह द्वारा प्रति-प्रवाह पार्श्व की परत दरारों को बंद करना ।

(4) पूर्वबलित केबलों द्वारा सात उच्च एकाश्मों को मजबूत करना ।

एक स्थायी उपाय के रूप में, कन्क्रीट बेकिंग द्वारा बांध को मजबूत करने की एक स्कीम को, कार्यान्विति के लिए, अन्तिम रूप दिया गया है ।

पर्याप्त सावधानी के तौर पर, महाराष्ट्र सरकार ने रेडियो सैटों द्वारा बाढ़ संबंधी चेतावनियां देने की एक आपातकालिक स्कीम तैयार की है ।

विद्युत परियोजना के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता

1642. **श्री भोला नाथ मास्टर :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विभाग का विचार राजस्थान को इतनी वित्तीय सहायता

देने का है जिससे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये विद्युत् की उनकी मांग चौथी योजना में ही पूरी हो सके ; और

(ख) राजस्थान में पहले ही क्रियान्वित की जा रही विद्युत् परियोजनाओं में से जो परियोजनायें चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरी नहीं होंगी उनको कब तक पूरा किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय केन्द्रीय ऋण सहायता राजस्थान सरकार को चंबल पन-बिजली परियोजनाओं (अर्थात् राणा प्रताप सागर और कोटा) और सतपुड़ा ताप-बिजली परियोजना पर, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सांझी स्कीमें हैं, होने वाले व्यय के अपने भाग को पूरा करन के लिये दी जा रही हैं। इस प्रकार की सहायता भाखड़ा और व्यास परियोजनाओं के लिये भी दी जा रही हैं जिसमें राजस्थान, पंजाब और राजस्थान भागीदार हैं। इसके अतिरिक्त परमाणु बिजली घर के लिये, जो राणा प्रताप सागर पर बन रहा है, केन्द्र सारा धन दे रहा है। उम्मीद है कि उन उत्पादन क्षमताओं से जो राजस्थान को इन परियोजनाओं से उपलब्ध होंगी, चौथी योजना के दौरान राजस्थान की मांगों की पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी।

(ख) व्यास परियोजना को छोड़ कर सारी निर्माणधीन स्कीमों के चौथी योजना-वधि में पूरा हो जाने की सम्भावना है। जहां तक व्यास परियोजना का सम्बन्ध है, देहर बिजली घर पर 165-165 मैगावाट के दो उत्पादन यूनिटों के 1973-74 तक, और 165-165 मैगावाट के शेष दो यूनिटों के 1974-75 तक चालू हो जाने की संभावना है। पोंग बिजली-घर में, 60-60 मैगावाट के दो यूनिटों के 1974-75 तक और 60-60 मैगावाट के शेष दो यूनिटों के 1975-76 चालू हो जाने की संभावना है।

परमाणु शक्ति केन्द्र, कोटा के लिये बिजली की सप्लाई

1643. **श्री भोला नाथ मास्टर** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य बिजली बोर्ड को केन्द्रीय सरकार से 1.5 करोड़ रुपये की राशि मिली है कि वह उदयपुर से डाबरी तक बिजली सप्लाई करे जिससे राजस्थान के कोटा में स्थित रावत भाटा परमाणु शक्ति से उपलब्ध बिजली का उपयोग किया जा सके और इसके लिये खंभे तथा तार लगाने का काम आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक स्थापनाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार बिजली मिल जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राज्य के अन्दर पोरषण पथों की कार्यान्विति के लिये, जिन में प्रस्तावित और विचाराधीन परमाणु बिजली केन्द्र से उत्पन्न हुई बिजली का वितरण भी शामिल है, कोई पृथक-रक्षित केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है। परन्तु राज्य बिजली बोर्ड, राज्य में अन्य उद्योगों तथा उपयोक्ताओं को बिजली सप्लाई करने के लिए पारेषण तथा वितरण पथों का निर्माण कार्य कर रहा है।

Construction of Rural Housing Unites

1644. **SHRI D.N. PATODIA :**
SHRI SARJOO PANDEY :
SHRI RAMACHANDRA VEERAPPA :
SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI :
SHRI N. K. SANGHI :
SHRI R. R. SINGH DEO :
SHRI JAGESHWAR YADAV:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMEMT be pleased to state :